

अंकिता के माता-पिता हिरासत में!

कार्यालय संवाददाता

नई दिल्ली। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय और कथित वीआईपी भूमिका की जांच की मांग को लेकर दिल्ली पहुंचे अंकिता के माता-पिता को गुरुवार तड़के दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इंडिया गेट पर रातभर चले धरने के बाद सुबह करीब चार बजे पुलिस ने कार्रवाई की। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस

◆ दुष्यंत की राज्यपाल नियुक्ति रोकने की मांग पर इंडिया गेट पर रातभर धरना
◆ राहुल और प्रियंका गांधी ने की मुलाकात, हिरासत के बाद किया गया रिहा
◆ 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए दुष्यंत गौतम की नियुक्ति रद्द करने की मांग

के कई नेता और अन्य प्रदर्शनकारी भी हिरासत में लिए गए। बाद में अंकिता के माता-पिता समेत हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा कर दिया गया।

इस घटनाक्रम ने उत्तराखंड के बहुचर्चित हत्याकांड को एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में ला दिया है। अपनी बेटी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर चार साल से संघर्ष कर रहे माता-पिता अब दिल्ली में भी सरकार से जवाब मांग रहे हैं। परिवार का विरोध भारतीय जनता पार्टी के नेता दुष्यंत कुमार गौतम को सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किए जाने के खिलाफ है। माता-पिता की मांग है कि मामले में कथित वीआईपी कोण की केंद्रीय



अन्वेषण ब्यूरो की जांच पूरी होने तक उनकी नियुक्ति रोक दी जाए।

इंडिया गेट पर धरने पर बैठे अंकिता के माता-पिता से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड़ा ने मुलाकात की। उनके साथ कांग्रेस नेता पवन खेड़ा समेत अन्य नेता भी मौजूद थे। राहुल गांधी ने इस मामले में सीबीआई जांच पूरी होने तक दुष्यंत गौतम की राज्यपाल के रूप में नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग उठाई। इस मुलाकात के बाद धरने ने राजनीतिक रूप से और व्यापक रूप ले लिया। हिरासत में लिए जाने से पहले अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी

ने सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए दुष्यंत गौतम की नियुक्ति रद्द करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर देशभर में विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं। अंकिता की मां सोनी देवी ने भी कहा कि नियुक्ति रद्द होने तक उनका विरोध जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें सार्वजनिक स्थान पर धरना देने की अनुमति नहीं मिलती, तो वह अपने घर पर भूख हड़ताल करेंगी।

कांग्रेस नेताओं ने पुलिस की कार्रवाई की आलोचना की। पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत और काजी निजामुद्दीन ने सवाल उठाया कि न्याय की मांग कर रहे परिवार

के साथ इस तरह की कार्रवाई क्यों की गई। कांग्रेस नेताओं ने पुलिस पर प्रदर्शनकारियों के साथ सख्ती करने के आरोप भी लगाए। हालांकि, इन आरोपों पर पुलिस का विस्तृत आधिकारिक पक्ष सामने आने की पुष्टि नहीं हुई है। 19 वर्षीय अंकिता भंडारी ऋषिकेश के निकट वनंता रिजार्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करती थीं। सितंबर 2022 में उनकी हत्या कर दी गई थी। 24 सितंबर 2022 को उनका शव चिल्ला नहर से बरामद हुआ। मामले में रिजार्ट संचालक पुलकित आर्य और उसके दो कर्मचारियों सौरभ भास्कर तथा अंकित गुप्ता को गिरफ्तार किया गया था। कोर्टद्वारा की

अदालत ने 30 मई 2025 को तीनों को हत्या और अन्य अपराधों में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

मामले में कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं। पिछले वर्ष सामने आए कुछ कथित ऑडियो के बाद यह मुद्दा फिर चर्चा में आया। अंकिता के माता-पिता का आरोप है कि इस पहलू की पूरी जांच होनी चाहिए। परिवार की ओर से दुष्यंत गौतम का नाम भी इस संदर्भ में लिया गया है, लेकिन यह आरोप अपने आप में किसी अपराध में उनकी संलिप्तता का प्रमाण नहीं है। उनकी ओर से इन आरोपों पर ताजा प्रतिक्रिया की पुष्टि नहीं हुई है। अंकिता के माता-पिता का इंडिया गेट पर धरना इस सवाल को फिर सामने लाता है कि अदालत से दोषियों को सजा मिलने के बाद भी परिवार किन पहलुओं पर जांच की मांग कर रहा है। उनकी वर्तमान मांग कथित वीआईपी कोण की जांच पूरी करने और दुष्यंत गौतम की नियुक्ति रोकने की है। हिरासत, रिहाई और 24 घंटे के अल्टीमेटम के बाद अब निगाहें सरकार की प्रतिक्रिया पर हैं। उत्तराखंड में यह मामला केवल एक आपराधिक घटना तक सीमित नहीं रहा है। यह महिला सुरक्षा, सत्ता की जवाबदेही और निष्पक्ष जांच की मांग से जुड़ा संवेदनशील मुद्दा बन चुका है। दिल्ली में माता-पिता की हिरासत ने इस बहस को और तेज कर दिया है।

अंकिता भंडारी के परिजनों की गिरफ्तारी पर कांग्रेस का राज्यपाल आवास कूच

संवाददाता

देहरादून। अंकिता भंडारी के माता पिता की गिरफ्तारी के विरोध को लेकर कांग्रेस ने आज राज्यपाल आवास कूच किया। जिनको बैरकेडिंग लगाकर रोक दिया गया। जिसके बाद कांग्रेसी पुलिस को गच्चा देकर राज्यपाल आवास के बाहर पहुंच गये जिसके बाद वह वहीं धरने पर बैठ गये।

आज दिल्ली में धरने पर बैठे अंकिता भंडारी के माता पिता को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने के विरोध में कांग्रेस ने राज्यपाल आवास कूच किया। कांग्रेस कार्यकर्ता जैसे ही हाथीबडकला चौकी के पास पहुंचे तो पुलिस ने बैरकेडिंग लगाकर उनको वहीं रोक दिया जिसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल सहित अन्य कांग्रेसी पुलिस को गच्चा देकर राज्यपाल आवास के बाहर पहुंच गये। जिसके बाद वह वहीं धरने पर बैठ



पुलिस को गच्चा देकर पहुंचे आवास के बाहर

गये। उनका कहना था कि भाजपा सरकार अपने नेताओं को बचाने में लगी है। जब भी सरकार से वीआईपी का नाम जानने का प्रयास किया गया तो भाजपा सरकार

पुलिस को आगे कर देती है। उन्होंने कहा कि अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे अंकिता भंडारी के माता पिता को दिल्ली पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया

गया वह एक दम गैरकानूनी है। अपनी बात रखने का सभी को संवैधानिक अधिकार है। धरने के दौरान नगर मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे जिनके माध्यम से राज्यपाल

को ज्ञापन प्रेषित किया गया। धरना देने वालों में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, प्रीतम सिंह, हरक सिंह रावत, लालचंद शर्मा आदि लोग शामिल रहे।

दून वैली मेल

संपादकीय

अंकिता प्रकरण पर सत्ता भयभीत

सत्ता इतनी कमजोर कब से हो गई कि एक बेटी के लिए न्याय मांगते मां-बाप उसकी ताकत को चुनौती देने लगे? सरकार के पास पुलिस है, प्रशासन है, कानून है, सत्ता का पूरा तंत्र है। दूसरी तरफ एक परिवार है, जिसने अपनी बेटी खोई है और अब उसके हिस्से का न्याय मांग रहा है। फिर इतना डर किस बात का है? कौन-सा ऐसा सवाल है, जिससे सत्ता की पेशानी पर बल पड़ रहे हैं? और कौन-सा ऐसा सच है, जिसे सामने आने से रोकने के लिए न्याय की गुहार लगाते परिवार को ही हिरासत में लेने की नौबत आ रही है? दिल्ली के इंडिया गेट पर अंकिता भंडारी के माता-पिता का धरना केवल एक परिवार का विरोध नहीं है। यह उस व्यवस्था के सामने खड़ा सवाल है, जो बड़े-बड़े मंचों से न्याय, नारी सम्मान और संवेदनशील शासन की बातें करती है, लेकिन जब एक पीड़ित परिवार अपनी मांग लेकर सामने आता है तो उसे सुनने के बजाय उसकी आवाज रोकने की तस्वीर सामने आती है। अंकिता के माता-पिता को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। सवाल यह नहीं कि पुलिस के पास कार्रवाई का अधिकार है या नहीं। सवाल यह है कि क्या इस अधिकार का इस्तेमाल न्याय मांगने वालों को चुप कराने के लिए किया जाना चाहिए? अंकिता भंडारी की हत्या ने पूरे उत्तराखंड को झकझोर दिया था। उन्नीस साल की युवती की जिंदगी छीन ली गई। मामले में अदालत ने तीन आरोपितों को दोषी ठहराकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कानून ने अपना काम किया, लेकिन अंकिता के माता-पिता के मन में कथित वीआइपी की भूमिका और जांच के कुछ पहलुओं को लेकर सवाल अब भी हैं। वह उन सवालों का जवाब चाहते हैं। वह जांच की मांग कर रहे हैं। वह चाहते हैं कि जिन आशंकाओं को लेकर वह लगातार आवाज उठा रहे हैं, उनका निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से निस्तारण हो। क्या यह मांग इतनी अनुचित है कि परिवार को हिरासत में लेना पड़े? क्या किसी आरोप की जांच मांगना अपराध है? क्या सरकार से सवाल पूछना व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह है? यदि आरोप निराधार हैं तो जांच और तथ्यों के आधार पर उनका जवाब दिया जाए। यदि कोई पहलू जांच के दायरे में है तो उसकी स्थिति स्पष्ट की जाए। लेकिन सवाल उठाने वालों को ही कठघरे में खड़ा कर देने से सवाल खत्म नहीं होते। वह और गहरे होते हैं। यह भी साफ रहना चाहिए कि किसी व्यक्ति का नाम किसी आरोप में लिया जाना उसे दोषी सिद्ध नहीं करता। कथित वीआइपी की भूमिका से जुड़े सवालों का फैसला राजनीतिक बयानबाजी नहीं, साक्ष्य और निष्पक्ष जांच ही कर सकते हैं। लेकिन निष्पक्ष जांच की मांग को ही दबा देने की कोशिश हो तो व्यवस्था की नीयत पर सवाल उठाना स्वाभाविक है। राजनीतिक मंचों पर महिला सम्मान के नारे लगाना आसान है। बेटियों की सुरक्षा को सरकार की प्राथमिकता बनाना भी आसान है। कठिन परीक्षा तब होती है, जब किसी बेटी के साथ हुई घटना व्यवस्था की जवाबदेही पर सवाल खड़े करती है। उस समय सरकार का व्यवहार बताता है कि उसके नारे कितने सच्चे हैं और संवेदनशीलता कितनी वास्तविक। अंकिता के नाम पर राजनीति करने वालों से भी सवाल होना चाहिए। विपक्ष यदि परिवार के साथ खड़ा है तो उसे केवल बयान जारी करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उसे तथ्यों के आधार पर जांच और जवाबदेही की मांग करनी चाहिए। लेकिन सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी इससे कहीं बड़ी है, क्योंकि शासन और प्रशासन की जवाबदेही उसी पर है। वह विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाकर अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकता। अंकिता का मामला किसी दल की चुनावी संपत्ति नहीं है। यह एक परिवार के न्याय, समाज के भरोसे और शासन की विश्वसनीयता का प्रश्न है। इसे राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप में उलझाकर मूल सवालों से बचने की कोशिश अंततः व्यवस्था को ही कमजोर करेगी। अंकिता के माता-पिता को आखिर दिल्ली के इंडिया गेट तक क्यों पहुंचना पड़ा? वह अपनी मांग लेकर अपने ही प्रदेश में संघर्ष करते रहे, अब देश की राजधानी में आवाज उठा रहे हैं। उनकी मांगों पर अब तक क्या कार्रवाई हुई? कथित वीआइपी कोण की जांच की वास्तविक स्थिति क्या है? परिवार को किन सवालों के जवाब नहीं मिले हैं? यदि जांच पूरी हो चुकी है तो उसके निष्कर्ष क्या हैं? यदि कुछ बाकी है तो उसे पूरा करने की समयसीमा क्या है? सह पह सवाल हैं, जिनका जवाब किसी राजनीतिक नारे से नहीं दिया जा सकता। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि परिवार की मांगों पर उसका रुख क्या है। पुलिस को हिरासत की कार्रवाई का आधार बनाना चाहिए। संबंधित जांच एजेंसी को कानून के दायरे में जांच की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। यही जवाबदेही है, यही पारदर्शिता है और यही जनता के विश्वास को बचाने का रास्ता है। सत्ता को यह भ्रम नहीं पालना चाहिए कि पुलिस की कार्रवाई से असहमति समाप्त हो जाएगी। सत्ता को समझना होगा कि न्याय की मांग करने वाले परिवार को हिरासत में लेकर वह अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। यदि कार्रवाई जरूरी थी तो उसका आधार सामने रखे। यदि जांच निष्पक्ष है तो उसके तथ्यों से भरोसा पैदा करे। और यदि परिवार की कोई मांग कानून के तहत पूरी नहीं की जा सकती तो उसका स्पष्ट कारण बताए। लोकतंत्र में जवाब की जगह आदेश और संवाद की जगह सख्ती लेने लगे तो नागरिक का भरोसा टूटता है। सबसे बड़ा सवाल यही है। अंकिता के माता-पिता की आवाज से सत्ता को डर किस बात का है? किसी आरोप से, किसी सवाल से या उस जवाबदेही से, जिससे बचने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए? एक बेटी की हत्या के बाद उसके माता-पिता को न्याय के लिए दर-दर भटकना पड़े, राजधानी में धरना देना पड़े और फिर हिरासत का सामना करना पड़े, तो यह केवल एक परिवार की पीड़ा नहीं, पूरी व्यवस्था के लिए चेतावनी है। सरकार को तय करना है कि वह इस पीड़ा का जवाब संवेदनशीलता और पारदर्शिता से देगी या सख्ती और चुप्पी से। क्योंकि पुलिस की ताकत से धरना हटाया जा सकता है, लेकिन न्याय का सवाल नहीं। आवाज पर पहरा बैठाया जा सकता है, लेकिन सवालों को कैद नहीं किया जा सकता। अंकिता के माता-पिता को चुप कराने से बेहतर है कि उनके सवालों का जवाब दिया जाए। आखिर लोकतंत्र में सत्ता जनता से बड़ी नहीं होती और न्याय की मांग सत्ता की मेहरबानी नहीं, नागरिक का अधिकार है।

अंकिता प्रकरण पर भाजपा का बचाव

कार्यालय संवाददाता
देहरादून। अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर उत्तराखंड की सियासत के केंद्र में है। पीड़ित परिवार की न्याय संबंधी मांगों और मामले को लेकर जारी राजनीतिक बहस के बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार के बचाव में उतर आए हैं। उन्होंने दावा किया कि घटना सामने आने के बाद सरकार ने त्वरित कार्रवाई, निष्पक्ष जांच, प्रभावी अभियोजन और पीड़ित परिवार को सहायता उपलब्ध कराने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए।

भट्ट ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी से लेकर विशेष जांच दल के गठन, अभियोजन की व्यवस्था और परिवार की मांगों पर निर्णय लेने तक सरकार की कार्रवाई का हवाला दिया। उनका संदेश स्पष्ट है कि भाजपा इस संवेदनशील प्रकरण पर सरकार के कामकाज को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब कार्रवाई के रिकार्ड के आधार पर देना चाहती है। लेकिन अंकिता प्रकरण में राजनीतिक बहस का असली केंद्र केवल यह नहीं है कि सरकार ने अब तक क्या-क्या कदम उठाए। सवाल यह भी है कि पीड़ित परिवार की मौजूदा मांगों, शंकाओं और न्याय को लेकर उठाए जा रहे सवालों का समाधान किस तरह होगा। यही वह बिंदु है, जहां भाजपा के बचाव और विपक्ष के हमलों के बीच राजनीतिक टकराव और तेज हो सकता है।

महेंद्र भट्ट ने मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में सरकार की कार्रवाई को रेखांकित करते हुए कहा कि मामले को गंभीरता से लिया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी, एसआईटी जांच और अभियोजन की व्यवस्था का उल्लेख कर भाजपा प्रदेश सरकार की भूमिका को प्रभावी और जवाबदेह बनाने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक दृष्टि से यह बयान महत्वपूर्ण है। अंकिता भंडारी प्रकरण केवल एक आपराधिक मामला नहीं, बल्कि उत्तराखंड में महिलाओं की सुरक्षा, सत्ता की जवाबदेही और न्याय व्यवस्था पर जनता के भरोसे से जुड़ा

◆भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने गिनाई धामी सरकार की कार्रवाई
◆विपक्ष के सवालों के बीच सरकार के समर्थन में जारे प्रदेश अध्यक्ष
◆महेंद्र भट्ट बोले-त्वरित गिरफ्तारी से एसआईटी तक का दिया हवाला

संवेदनशील मुद्दा है। ऐसे में भाजपा नेतृत्व का सरकार के समर्थन में सामने आना बताता है कि पार्टी इस मामले को लेकर बनने वाली राजनीतिक धारणा को गंभीरता से ले रही है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने पीड़ित परिवार की मांगों पर निर्णय लेने का भी उल्लेख किया। हालांकि, इस दावे के साथ यह स्पष्ट होना जरूरी है कि परिवार की वर्तमान मांगें क्या हैं, किन मांगों पर क्या कार्रवाई हुई और किन मुद्दों पर अब भी संवाद या स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। किसी भी संवेदनशील प्रकरण में सरकार की कार्रवाई

का मूल्यांकन केवल उसके दावों से नहीं, बल्कि उपलब्ध तथ्यों, न्यायिक प्रक्रिया और पीड़ित परिवार के सवालों के समाधान से होना चाहिए। परिवार की मांगों पर सरकार का पक्ष महत्वपूर्ण है, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण यह भी है कि परिवार स्वयं अपनी स्थिति और अपेक्षाएं सामने रख सके।

अंकिता प्रकरण को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक टकराव की संभावना बनी हुई है। भाजपा सरकार की कार्रवाई गिनाकर अपने पक्ष को मजबूत करना चाहती है, जबकि विपक्ष के लिए पीड़ित परिवार की न्याय संबंधी मांगें सरकार से जवाब मांगने का आधार बन सकती हैं। इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों की परीक्षा भी है। भाजपा को अपने दावों के समर्थन में तथ्य सामने रखने होंगे, जबकि विपक्ष को भी आरोपों को प्रमाण और ठोस सवालों के आधार पर उठाना होगा। किसी पीड़ित परिवार की पीड़ा को केवल राजनीतिक लाभ-हानि के तराजू पर तौलना न्याय के मूल प्रश्न को पीछे धकेल सकता है।

उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 की ओर बढ़ती राजनीति के बीच अंकिता भंडारी प्रकरण का महत्व और बढ़ जाता है। महिला सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और सरकार की संवेदनशीलता जैसे मुद्दे चुनावी विमर्श को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का बयान सरकार की उपलब्धियों को सामने रखने के साथ-साथ इस मुद्दे पर पार्टी का राजनीतिक पक्ष

►► शेष पृष्ठ 7 पर

सियासत में ‘खौफ’ कठघरे में सत्ता

कार्यालय संवाददाता
देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में अब सवाल केवल सत्ता और विपक्ष की लड़ाई का नहीं, बल्कि एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि की सुरक्षा और व्यवस्था पर उसके भरोसे का भी है। हल्लदानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश का भावुक होकर रो पड़ना, अपनी और अपने परिवार की जान को खतरा बनाना और प्रदेश में नेताओं के फोन टैप किए जाने का आरोप लगाना धामी सरकार के लिए असहज करने वाला घटनाक्रम है। विधायक ने अपनी गाड़ी का हादसा कराए जाने की आशंका भी जताई है। इतना ही नहीं, गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान कठोर कदम उठाने की चेतावनी देकर उन्होंने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है।

सवाल सीधा है- उत्तराखंड में एक विधायक को आखिर किससे खतरा महसूस हो रहा है? क्या यह किसी वास्तविक सुरक्षा संबंधी चिंता का मामला है, किसी कथित साजिश की आशंका है या फिर प्रदेश की राजनीति में बढ़ते अविश्वास का विस्फोट? इन सवालों के जवाब जांच से ही सामने आएंगे, लेकिन सुमित हृदयेश के आरोपों ने सरकार और पुलिस प्रशासन को जवाबदेही के कठघरे में जरूर खड़ा कर दिया है। सुमित हृदयेश कोई आम राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं, बल्कि जनता द्वारा चुने गए विधायक हैं। जब ऐसा जनप्रतिनिधि सार्वजनिक रूप से अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर आशंका जताता है, तो उसके बयान को सामान्य राजनीतिक आरोप कहकर खारिज करना आसान नहीं होना चाहिए। खासकर तब, जब वह फोन टैपिंग जैसे गंभीर मुद्दे

को उठाते हुए संभावित दुर्घटना की आशंका भी व्यक्त कर रहा हो।

यहां सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल यही है कि क्या सरकार विधायक की शिकायत को गंभीरता से लेकर स्थिति स्पष्ट करेगी या विपक्ष के आरोपों को राजनीतिक स्टंट बताकर पल्ला झाड़ लेगी? सत्ता के लिए यह मामला इसलिए भी संवेदनशील है, क्योंकि सुरक्षा और कानून-व्यवस्था सरकार की सबसे बुनियादी जिम्मेदारियों में शामिल

◆रोते हुए कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश की गुहार, मेरी और परिवार की जान को खतरा
◆फोन टैपिंग से गाड़ी का एक्सीडेंट कराने की आशंका तक, गैरसैंण में फूटेगा सियासी बम
◆हल्लदानी से कांग्रेस विधायक ने अपनी गाड़ी का हादसा कराए जाने की आशंका भी जताई

हैं। विधायक ने प्रदेश में एक बड़े गिरोह द्वारा नेताओं के फोन टैप किए जाने का दावा किया है। यदि इस आरोप के पीछे कोई ठोस साक्ष्य है, तो यह केवल कांग्रेस या भाजपा के बीच का विवाद नहीं रह जाता। मामला नागरिकों की निजता, राजनीतिक स्वतंत्रता और सरकारी तंत्र के संभावित दुरुपयोग तक पहुंच सकता है।

लेकिन आरोप जितना गंभीर है, उतना ही जरूरी उसका प्रमाणित होना भी है। फोन टैपिंग किसने की, किसके निर्देश पर की और क्या इसके लिए कानूनी अनुमति थी कि इन सवालों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सरकार को आरोपों पर स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए और पुलिस को शिकायत मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई करनी

चाहिए। यदि आरोप निराधार हैं, तो जांच उन्हें खारिज करे। यदि उनमें तथ्य हैं, तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो। लोकतंत्र में गंभीर आरोपों का जवाब चुप्पी या राजनीतिक पलटवार नहीं, बल्कि पारदर्शिता है। सुमित हृदयेश ने अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट कराए जाने की आशंका जताकर विवाद को और गंभीर बना दिया है। यह आशंका अपने आप में किसी साजिश का प्रमाण नहीं है, लेकिन इसे अनदेखा करना भी उचित नहीं होगा। पुलिस को विधायक की शिकायत, उपलब्ध तथ्यों और सुरक्षा संबंधी जोखिम का आकलन करना चाहिए।

यदि किसी जनप्रतिनिधि को अपनी आवाजाही और परिवार की सुरक्षा को लेकर वास्तविक खतरा महसूस हो रहा है, तो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह उनकी बात सुने और आवश्यक सुरक्षा उपायों पर निर्णय ले। साथ ही, बिना साक्ष्य किसी व्यक्ति या संगठन को दोषी ठहराने से बचना भी जरूरी है। गैरसैंण विधानसभा सत्र से पहले सुमित हृदयेश की चेतावनी ने इस पूरे मामले को राजनीतिक रूप से और विस्फोटक बना दिया है। यदि कांग्रेस इस मुद्दे को सदन में उठाती है, तो सरकार को विधायक की सुरक्षा, फोन टैपिंग के आरोप और शिकायतों पर हुई कार्रवाई को लेकर सवालों का सामना करना पड़ सकता है।

कांग्रेस के लिए यह सरकार को घेरने का बड़ा अवसर है। पार्टी कानून-व्यवस्था और विपक्षी नेताओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाकर सरकार की जवाबदेही तय करने की मांग कर सकती है। वहीं, भाजपा और सरकार के सामने चुनौती होगी कि वह

►► शेष पृष्ठ 7 पर

एसआईआर से बदला 'चुनावी गणित'

कार्यालय संवाददाता
देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण ने प्रदेश की सियासत में नई बहस छेड़ दी है। खासकर मुस्लिम बहुल और मुस्लिम मतदाताओं के प्रभाव वाली मानी जाने वाली विधानसभा सीटों पर 2022 के चुनाव के समय की मतदाता सूची और एसआईआर के बाद सामने आए आंकड़ों के बीच बड़ा अंतर राजनीतिक दलों का ध्यान खींच रहा है। हरिद्वार, देहरादून, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल जैसे जिलों में मतदाताओं की संख्या में उल्लेखनीय कमी दर्ज होने के बाद भाजपा और कांग्रेस सहित तमाम दलों को अपने पुराने चुनावी आकलन की नए सिरे से समीक्षा करनी पड़ रही है।

इस बदलाव का राजनीतिक महत्व इसलिए भी बढ़ गया है, क्योंकि उत्तराखंड में कई सीटों पर जीत-हार का अंतर अपेक्षाकृत कम रहा है। ऐसे में मतदाता सूची में बदलाव का असर चुनावी रणनीति पर पड़ना स्वाभाविक है। हालांकि, मतदाताओं की कुल संख्या में कमी अपने आप में यह साबित नहीं करती कि किसी खास समुदाय के मतदाताओं के नाम ही अधिक हटे हैं या किसी राजनीतिक दल को इसका सीधा लाभ मिलेगा। इसके लिए विधानसभा क्षेत्र और बूथ स्तर के विस्तृत आंकड़ों की जरूरत होगी।

2022 के विधानसभा चुनाव के समय इस्तेमाल की गई मतदाता सूचियों की तुलना एसआईआर के बाद की सूचियों से

करने पर देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल जिलों में बड़ा अंतर सामने आया है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, इन चार जिलों में 2022 में कुल 49,87,332 मतदाता थे, जबकि पुनरीक्षण के बाद यह संख्या 42,86,021 रह गई। दोनों आंकड़ों के बीच 7,01,311 मतदाताओं का अंतर है। देहरादून जिले में 2022 के 14,87,775 मतदाताओं के मुकाबले संशोधित सूची में 11,90,805 मतदाता दर्ज किए गए। हरिद्वार में यह संख्या 14,20,182 से घटकर 12,46,219, ऊधमसिंह नगर में 13,03,476 से घटकर 11,55,672 और नैनीताल में 7,75,899 से घटकर 6,93,325 रह गई।

इन आंकड़ों ने राजनीतिक दलों के सामने मतदाता सूची के बदलावों को समझने की चुनौती खड़ी कर दी है। हालांकि, 2022 की सूची और 2026 की सूची के बीच का पूरा अंतर केवल एसआईआर में नाम हटाए जाने का आंकड़ा नहीं माना जा सकता। दोनों सूचियों के बीच समयांतराल में नए नाम जुड़ने, मृत्यु, स्थायी रूप से स्थानांतरित होने, दोहरी प्रविष्टियों और अन्य संशोधनों की भूमिका भी हो सकती है। हरिद्वार जिले की पिरान कलियर, मंगलौर, भगवानपुर और खानपुर जैसी सीटों के साथ देहरादून तथा ऊधमसिंह नगर के कुछ विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका को लेकर राजनीतिक दल विशेष रूप से आकलन करते रहे हैं। एसआईआर के बाद मतदाता

संख्या में आए बदलाव ने इन सीटों पर चुनावी समीकरणों की समीक्षा को महत्वपूर्ण बना दिया है।

हरिद्वार जिले में पिरान कलियर में 2022 के 1,27,118 मतदाताओं के मुकाबले संशोधित सूची में 1,16,187 मतदाता दर्ज किए गए। मंगलौर में यह संख्या 1,15,978 से घटकर 1,07,424

♦ उत्तराखंड में मुस्लिम बहुल सीटों पर नए सिरे से विधेयी अब सियासी विसात
♦ 2022 की मतदाता सूची और एसआईआर के बाद के आंकड़ों में बड़ा अंतर
♦ हरिद्वार से ऊधमसिंह नगर तक भाजपा और कांग्रेस की रणनीति की होगी परीक्षा
♦ चुनाव से पहले मतदाता सूची में बदलाव ने बढ़ाई राजनीतिक दलों की चिंता

और भगवानपुर में 1,23,476 से घटकर 1,17,044 रह गई। इन आंकड़ों के आधार पर किसी समुदाय के मतदाताओं की संख्या में वास्तविक कमी या उसके चुनावी प्रभाव का निष्कर्ष निकालना अभी जल्दबाजी होगा। इसके लिए यह जानना जरूरी है कि हटाए गए नाम किन कारणों से हटे, कितने पात्र मतदाताओं ने दोबारा नाम दर्ज करने के लिए आवेदन किया और कितने नाम अंतिम सूची में बहाल हुए।

एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस ने मतदाता सूची से नाम हटाए जाने पर सवाल उठाए हैं। पार्टी का आरोप है कि पुनरीक्षण का प्रभाव मुस्लिम मतदाताओं वाले क्षेत्रों में अधिक दिखाई दे रहा है।

दूसरी ओर, भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को राजनीतिक बयानबाजी करार देते हुए चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भरोसा जताया है। इस विवाद के बीच असल सवाल यह है कि निर्वाचन विभाग विधानसभा क्षेत्रवार और बूथवार आंकड़ों के आधार पर स्थिति को कितना स्पष्ट करता है। लोकतंत्र में मतदाता सूची का शुद्ध होना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी यह सुनिश्चित करना भी है कि कोई पात्र नागरिक केवल सत्यापन या दस्तावेजी प्रक्रिया की कठिनाइयों के कारण मतदान के अधिकार से वंचित न रह जाए।

2022 के विधानसभा चुनाव में कुछ सीटों पर जीत का अंतर काफी कम था। ऐसे क्षेत्रों में मतदाता सूची के बदलावों की पड़ताल राजनीतिक दलों के लिए विशेष महत्व रखती है। उदाहरण के तौर पर, हरिद्वार ग्रामीण में कांग्रेस की अनुपमा रावत ने भाजपा के स्वामी यतीश्वरानंद को 4,472 मतों से हराया था, जबकि मंगलौर में भी मुकाबला करीबी रहा था। ऐसे चुनावी इतिहास वाले क्षेत्रों में दल पुराने बूथवार मतदान, नए मतदाताओं और संशोधित सूची के आंकड़ों का मिलान कर अपनी रणनीति तय करना चाहेंगे। लेकिन मतदाता सूची में कमी को सीधे किसी पार्टी की जीत या हार से जोड़ना उचित नहीं होगा। हटाए गए सभी मतदाता मतदान करने वाले थे या नहीं, वह किस राजनीतिक दल का समर्थन करते थे और उनमें से कितने पात्र मतदाता अब सूची से बाहर हैं। इन सवालों

के उत्तर के बिना किसी निश्चित चुनावी निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं है।

उत्तराखंड में 2027 का विधानसभा चुनाव भाजपा और कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई होगा। ऐसे में एसआईआर के बाद मतदाता सूची में हुए बदलाव राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बने रह सकते हैं। भाजपा जहां सूची के शुद्धिकरण और चुनावी व्यवस्था की विश्वसनीयता पर जोर दे सकती है, वहीं कांग्रेस पात्र मतदाताओं के नाम सुरक्षित रखने और कथित अनियमितताओं की जांच को मुद्दा बना सकती है। निर्वाचन आयोग के सामने इस समय दोहरी जिम्मेदारी है कि मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाना और यह सुनिश्चित करना कि किसी पात्र मतदाता का नाम गलत तरीके से बाहर न रहे। पारदर्शी आंकड़े, शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण और नाम जोड़ने की सरल प्रक्रिया इस बहस को तथ्यात्मक आधार दे सकते हैं। निष्कर्ष यही है कि एसआईआर ने चुनावी गणित की समीक्षा की जरूरत जरूर बढ़ाई है, लेकिन 2027 की जीत-हार का फैसला अभी इन आंकड़ों से नहीं लिखा जा सकता। असली तस्वीर तब साफ होगी, जब विधानसभा क्षेत्रवार और बूथवार बदलावों के कारण सामने आएंगे और पात्र मतदाताओं के नामों की स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए चुनौती पुराने चुनावी आंकड़ों पर भरोसा करने के बजाय बदली हुई मतदाता सूची की तथ्यात्मक पड़ताल करना है।

हाईवे पर धीमी गति से हो रहे निर्माण

कोटद्वार (आरएनएस)। विकासखंड मुख्यालय में लगे बहुउद्देशीय शिविर में 10 धात्रियों को महालक्ष्मी किट, एक दिव्यांग को व्हीलचेयर और महिला समूह को कृषि यंत्र वितरित किए गए। विभिन्न विभागों की ओर से स्टॉल लगाकर लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान हाईवे पर निर्माण कार्य की धीमी गति और सड़कों के निर्माण का मुद्दा भी उठाया गया।

साझासँग स्थित ब्लॉक सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्य औषधि पादप बोर्ड की उपाध्यक्ष एवं दायित्वधारी राज्यमंत्री अनुराधा बालिया ने कहा कि लोगों को समस्याएं संबंधित विभागों के अधिकारियों के सामने रखनी चाहिए ताकि उनका त्वरित समाधान हो सके।

उन्होंने कहा कि जनसमस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष भी रखा जाएगा। कृषि विभाग की ओर से चयनित जै भैरों बाबा समूह मोहरा को पावर वीडर, चॉप कटर और ब्रश कटर समेत कृषि यंत्र दिए गए। शिविर में ज्येष्ठ उप प्रमुख सुनील नेगी ने हाईवे पर निर्माण कार्य की धीमी गति का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इससे काफी परेशानी हो रही है।

उमरैला की ग्राम प्रधान संगीता देवी ने उमरैला-चरेख मार्ग पर झाड़ियों और अंधूरी नालियों से आवाजाही में खतरा होने की बात कही। लोनिवि के एई कपिल कुमार ने झाड़ियों की सफाई का आश्वासन दिया। सिमलचौड़ की प्रधान रजनी देवी ने दुगड्डा-गोदी छोटी के बीच स्टेट हाईवे-9 पर जल निकासी की व्यवस्था करने, गुनी बस्यूर को सड़क से जोड़ने, जिला पंचायत सदस्य सीमा भंडारी ने हनुमंती-चंडा मार्ग से मलबा हटाने की मांग उठाई।

इस अवसर पर एबीडीओ राजेश ध्यानी, एडीओ पंचायत जयदीप सिंह रावत, प्रशासनिक अधिकारी उमेश कंडवाल, ऊर्जा निगम की ईई नंदिता अग्रवाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, बैंक प्रतिनिधि और महिला समूहों के सदस्य मौजूद रहे।

वैधानिक सूचना

सुविज्ञ पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी विज्ञापन में दिए गए तथ्यों, शर्तों और दावों के प्रति वह खुद भी आश्वस्त हो लें। पाठकों से आग्रह है कि वह प्रकाशित विज्ञापन से प्रभावित होकर कोई कदम उठाने से पहले अपने स्तर पर भी स्वयं के संतुष्ट होने तक संपूर्ण व्यावहारिक जानकारी कर लें। भविष्य में किसी भी प्रकाशित विज्ञापन व लेख में निहित दावों या शर्तों को लेकर पाठकगण को कोई असुविधा या परेशानी होती है तो सांध्य दैनिक दून वैली मेल के मुद्रक, प्रकाशक या सम्पादक की कोई जवाबदेही नहीं होगी।

—प्रबंधक विज्ञापन

बहुउद्देशीय शिविर में दर्ज की 75 समस्याएं

चम्पावत (आरएनएस)। तल्ला पाल बिलौना के दूरस्थ क्षेत्र खटोली तल्ली में बहुउद्देशीय शिविर लगाया गया।

शिविर में 75 समस्याएं उठी। सीडीओ अजय सिंह ने अधिकारियों को समस्या समाधान के निर्देश दिए। चम्पावत के दूरस्थ क्षेत्र खटोली तल्ली के आनंदपुरी इंटर कॉलेज बहुउद्देशीय शिविर लगाया।

शिविर में विभिन्न विभागों के माध्यम से 610 लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया। स्वास्थ्य विभाग ने 82, आयुर्वेदिक ने 65, होम्योपैथिक ने 55,

पशुपालन ने 52, उद्यान ने 39 और कृषि विभाग ने 25 लोगों को लाभ पहुंचाया। राजस्व विभाग ने 37 लोगों के विभिन्न प्रमाण पत्र बनाए।

प्रकाश सिंह, मनोज सिंह व उत्तम सिंह ने राउमावि खटोली में पेयजल, लक्ष्मण सिंह ने चेकडैम, अनीता देवी ने नौला मरम्मत, हयात सिंह ने फसल सुरक्षा, भरत सिंह ने गोशाला में चहादीवारी, भागीरथी देवी ने खेल मैदान तथा राम सिंह ने आर्थिक सहायता देने की मांग की। कृषक

बबलू सिंह और छत्तर सिंह को ब्याज मुक्त ऋण दिया। मदन सिंह कली देवी को श्रवण यंत्र दिए।

यहां दर्जा धारी मुकेश महाराना, प्रमुख अंचला बोहरा, सुंदर बोहरा, रहीश सिंह, भागीरथी देवी, बीडीओ रमेश जोशी, एसीएमओ डॉ. इंद्रजीत पांडेय, सीएओ डी कुमार, सीवीओ डॉ. वसुंधरा गर्ब्याल, तहसीलदार बृजमोहन आर्य, भू-संरक्षण अधिकारी नारायण सिंह, डीएसओ प्रियंका भट्ट, डीओ जसवंत खड़ायत आदि मौजूद रहे।

बजट बैठक में प्रक्रियागत कमियों पर भड़के क्षेत्र पंचायत सदस्य

बागेश्वर (आरएनएस)। विकासखंड सभागार में बजट एवं कार्ययोजना को लेकर आयोजित बैठक में प्रक्रियागत कमियों के आरोप लगाते हुए क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने नाराजगी जताई। ज्येष्ठ उप प्रमुख मनीष कुमार टम्टा समेत सदस्यों ने आरोप लगाया कि बैठक से पहले क्षेत्र पंचायत की विधिवत बैठक नहीं बुलाई गई और न ही विकास योजनाओं के प्रस्ताव लेकर उन पर चर्चा की गई।

उन्होंने बैठक स्थगित कर नियमानुसार प्रक्रिया पूरी करने के बाद दोबारा आयोजित करने की मांग की। सदस्यों ने कहा कि बैठक में विकास योजनाओं पर विचार-विमर्श करने के बजाय केवल नाम और पद के सामने हस्ताक्षर कराए जा रहे थे। इससे सदस्यों के अधिकारों और उनके क्षेत्रों की विकास संबंधी जरूरतों की अनदेखी होने की आशंका है। उन्होंने कहा

कि बजट और कार्ययोजना तय करने से पहले सभी निर्वाचित सदस्यों के प्रस्तावों पर चर्चा कर उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। सदस्यों ने ब्लॉक प्रमुख की ओर से करीब 80 से 90 घोषणाएं किए जाने और लगभग 50 लाख रुपये की सोलर लाइट योजना का प्रस्ताव रखे जाने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि इन घोषणाओं और प्रस्तावों को किस शासनादेश और नियम के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है।

सदस्यों का आरोप था कि बैठक में करीब 20 लाख रुपये की घोषणाओं को लेकर बजट पर चर्चा हुई, जबकि उनकी योजनाओं के लिए उपलब्ध बजट कम कर अन्य कार्यों में धनराशि खर्च किए जाने की स्थिति सामने आ रही है। उन्होंने बजट आवंटन की स्थिति स्पष्ट करने और सभी क्षेत्रों की विकास जरूरतों को समान

महत्व देने की मांग की। सदस्यों ने कहा कि सामान्य बैठकों और अन्य कार्यक्रमों की सूचना ग्राम विकास अधिकारियों के माध्यम से नियमित रूप से दी जाती रही है, लेकिन बजट एवं कार्ययोजना जैसी महत्वपूर्ण बैठक में सूचना और प्रक्रिया के स्तर पर लापरवाही बरती गई। करीब 13 क्षेत्र पंचायत सदस्यों की मौजूदगी में उन्होंने बजट, कार्ययोजना और प्रस्तावों के निर्धारण में पारदर्शिता बरतने तथा सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर निर्णय लेने की मांग की। बैठक की प्रक्रिया पर आपत्ति जताने वालों में रवि रावत, भगवान भंडारी, निर्मल साह, कुशल धनिक, भारती रावत, सुनील जोशी, काजल आर्या, बहादुर सिंह, मनीष कुमार प्रसाद, रमेश राम, दीपा देवी और ज्येष्ठ उप प्रमुख मनीष कुमार टम्टा सहित अन्य सदस्य शामिल रहे।

खाना बनाते समय इन बातों का रखें खास ध्यान, सेहत को होगा फायदा

खाना बनाना एक कला है, जिसमें सिर्फ तेल का इस्तेमाल ही नहीं होता। सही तरीके से खाना बनाकर हम अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने खाने को और भी सेहतमंद बना सकते हैं। इन तरीकों से आप न केवल स्वाद बढ़ा सकते हैं, बल्कि पोषण भी सुधार सकते हैं। आइए जानें कि कैसे आप रोजमर्रा की रसोई में छोटे-छोटे बदलाव कर सकते हैं।

तेल का सही उपयोग करें : खाना बनाते समय तेल का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। ज्यादा तेल से न केवल खाने का स्वाद बिगड़ता है बल्कि सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। कोशिश करें कि खाना बनाते समय कम तेल का इस्तेमाल करें और उसे बार-बार न गर्म करें। इससे न केवल आपका खाना सेहतमंद रहेगा बल्कि आपके शरीर को अतिरिक्त चर्बी से भी छुटकारा मिलेगा। सही मात्रा में तेल का उपयोग करने से स्वाद और स्वास्थ्य दोनों में संतुलन बना सकते हैं।

सब्जियों को भूनने का तरीका बदलें : सब्जियों को भूनते समय अक्सर लोग ज्यादा तेल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे खाना तला हुआ सा लगने लगता है और उसमें अतिरिक्त कैलोरी शामिल हो जाती है। इसकी बजाय आप सब्जियों को भूनने के लिए थोड़े पानी का उपयोग कर सकते हैं या ऐसे बर्तन में पकाएं जो चिपकता न हो। इससे न केवल कैलोरी कम होगी बल्कि सब्जियों का प्राकृतिक स्वाद भी बना रहेगा। इस तरह आपका खाना सेहतमंद और स्वादिष्ट बनेगा।

मसालों का सही मिश्रण बनाएं : मसाले खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ उन्हें पौष्टिक भी बनाते हैं, लेकिन कभी-कभी ज्यादा मसाले खाने का स्वाद बिगाड़ सकते हैं और पाचन पर असर डाल सकते हैं। इसलिए मसालों का सही मिश्रण बनाना जरूरी है ताकि आपका खाना न केवल स्वादिष्ट बल्कि पौष्टिक भी हो। हल्दी, जीरा, धनिया जैसे मसालों का सही अनुपात मिलाकर इस्तेमाल करने से आपका खाना सेहतमंद बना रहेगा और पाचन पर भी कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा।

नमक का सही उपयोग करें : नमक हमारे खाने का अहम हिस्सा है, लेकिन इसका अधिक उपयोग हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। ज्यादा नमक खाने से रक्तचाप बढ़ सकता है और दिल की बीमारी का खतरा भी बढ़ता है। इसलिए नमक का सही मात्रा में उपयोग करना बहुत जरूरी है। खाने में स्वाद लाने के लिए आप सेंधा नमक या काला नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सेहत के लिए बेहतर होते हैं और स्वाद में भी अच्छे लगते हैं।

क्यों खत लिखते रहना चाहिए ? जानिए 5 कारण

आजकल ईमेल और संदेशों के दौर में खत लिखना एक पुरानी आदत लगती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि खत लिखना क्यों जरूरी है? आज के डिजिटल युग में भी खत लिखने की अपनी अहमियत है। यह न केवल हमारे विचारों को साफ तरीके से व्यक्त करने में मदद करता है, बल्कि हमारे रिश्तों को भी मजबूत बनाता है। आइए जानते हैं कि खत लिखने के 5 अहम कारण क्या हैं।

भावनाओं को व्यक्त करने का बेहतरीन तरीका : खत लिखना एक ऐसा माध्यम है, जिससे हम अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। कई बार हम सीधे सामने बोलने में झिझकते हैं या सही शब्द नहीं खोज पाते, लेकिन लिखित रूप में हम पूरी सोच-समझ के साथ अपने विचार रख सकते हैं। इससे हमारा संदेश साफ और स्पष्ट रहता है। इसके अलावा लिखित शब्दों में भावनाओं का गहरा असर होता है, जो कभी-कभी मौखिक शब्दों में नहीं हो पाता।

यादों को संजोने का तरीका : खत लिखने से हम अपने अनुभवों और यादों को संजो सकते हैं। जब हम किसी खास पल को लिखते हैं तो वह पल हमारे मन में हमेशा के लिए जीवित रहता है। चाहे वह किसी खास दोस्त को लिखा गया पत्र हो या परिवार के सदस्य को भेजा गया संदेश, हर पत्र एक कहानी बयां करता है। इन पत्रों को भविष्य में पढ़कर हम उन यादों को फिर से जी सकते हैं और अपने अतीत को याद कर सकते हैं।

रचनात्मकता को बढ़ावा देने का साधन : खत लिखना एक रचनात्मक प्रक्रिया होती है, जिसमें हम अपने विचारों को सजावट कर सकते हैं। रंग-बिरंगे कागज, सुंदर पेन और आकर्षक लिखावट का उपयोग करके हम अपने पत्रों को खास बना सकते हैं। इसके अलावा लिखते समय हमें शब्दों का सही चयन करना पड़ता है, जिससे हमारी शब्दावली भी बढ़ती है। इस प्रकार खत लिखना न केवल संवाद का माध्यम है बल्कि रचनात्मकता को भी बढ़ावा देता है।

संबंधों को मजबूत बनाने में मददगार : खत लिखने से हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। जब हम किसी को पत्र लिखते हैं तो वह व्यक्ति महसूस करता है कि हम उसकी परवाह करते हैं और उसके बारे में सोचते हैं। इससे हमारे संबंध अधिक गहरे और स्थायी बनते हैं। इसके अलावा खतों के माध्यम से हम अपने प्रियजनों से जुड़े रहते हैं और उनकी जिंदगी की छोटी-बड़ी बातों को जान पाते हैं।

आत्म-अनुशासन विकसित करने का तरीका : नियमित रूप से खत लिखना एक अच्छी आदत होती है, जो आत्म-अनुशासन विकसित करने में मदद करती है। जब हम नियमित रूप से किसी को पत्र लिखते रहते हैं तो यह हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है और हमें समय प्रबंधन सीखने में मदद मिलती है। इस प्रकार खत लिखना केवल एक पुरानी आदत नहीं बल्कि कई लाभों से भरी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है।

हर बार सीने में दर्द हार्ट अटैक नहीं होता, हो सकती है फेफड़ों से जुड़ी ये बीमारी

आमतौर पर हार्ट अटैक का सबसे बड़ा संकेत सीने में दर्द होना होता है। लेकिन सीने में दर्द केवल हार्ट अटैक हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि कई मामलों में यह बात सामने आई है कि सीने में दर्द की समस्या का कनेक्शन फेफड़ों से भी हो सकता है और इसके कारण हार्ट अटैक से भी गंभीर स्थिति हो सकती है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि सीने में दर्द फेफड़ों की किस बीमारी की ओर संकेत करता है और हमें इससे कैसे बचना चाहिए।

साधारण सीने में दर्द हो सकता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म

पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक फेफड़ों की स्थिति है, जिसमें लंग्स में ब्लड क्लॉट बन जाते हैं। यह फेफड़ों की आर्टरी में ब्लड सर्कुलेशन को रोकते हैं। ज्यादातर ब्लड क्लॉट पैरों की नसों से शुरू होकर फेफड़ों तक जाता है और यह स्थिति काफी गंभीर होती है। अगर किसी को बार-बार सीने में दर्द हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ है, चलने फिरने या बोलने में सांस फूलती है या दिक्कत होती है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए क्योंकि यह लंग्स क्लॉटिंग के कारण हो सकता है।

फेफड़ों में क्लॉटिंग के लक्षण

फेफड़ों में क्लॉटिंग होने के सामान्य लक्षणों में सांस लेने में कठिनाई होना, सीने में दर्द होना, बेहोश हो जाना, हार्टबीट का कंट्रोल न रहना, तेज दिल का धड़कना, पसीना आना, बुखार आना और पैरों में सूजन होना आम है।

लंग क्लॉट और हार्ट अटैक में अंतर

लंग्स क्लॉट की कंडीशन में आपको ऐसा महसूस होगा जैसे दिल का दौरा पड़ रहा हो, इसमें दर्द अक्सर तेज होता है और जब आप गहरी सांस लेते हैं तो दर्द और

ज्यादा बढ़ जाता है। इतना ही नहीं खाते, छींकते या झुकते समय भी फेफड़े या सीने में अजीब सा दर्द होता है।

लंग्स क्लॉट से कैसे बचें

अब बात आती है कि लंग्स क्लॉट से कैसे बचा जा सकता है, तो इससे बचने के लिए आपको एक बैलेंस डाइट लेना बहुत जरूरी है, फिजिकली फिट और एक्टिव रहना चाहिए। स्मोकिंग से बचना चाहिए, लंबे समय तक क्रॉस करके नहीं बैठना चाहिए, टाइट फिटिंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए और वजन को नियंत्रित करना चाहिए।



ऑनलाइन ज्वैलरी शॉपिंग करने के नुकसान!

आजकल ज्यादातर ग्राहक ज्वैलरी की ऑनलाइन शॉपिंग की ओर आकर्षित हो रहे हैं, पर गहनों की ऑनलाइन शॉपिंग करने से पहले आपको इसके नुकसान के बारे में भी पूरी जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। ज्वैलरी खरीदने से पहले अच्छे से सब मालूम कर लें कि अगर वह टूटी हुई निकलती है तो उसकी वापसी की सुविधा है या नहीं।

इस बात की जानकारी हासिल कर लें कि रास्ते में होने वाले नुकसान के लिए कम्पनी ने बीमा करवाया है या नहीं। ज्वैलरी की रसीद, क्वालिटी सर्टिफिकेट और वारंटी कार्ड लेना ना भूलें। हीरे या अन्य कीमती रत्नों की ज्वैलरी खरीदते वक्त खास ख्याल रखें कि उसके साथ किसी मान्यता

प्राप्त जेमोलॉजी संस्थान का प्रमाणपत्र है या नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि ज्वैलरी आपके बजाए गए माप के अनुरूप ठीक नहीं होती या ज्वैलरी का जो डिजाइन वेबसाइट पर दिखाया गया था, सही में आपको उससे अलग डिजाइन की ज्वैलरी भेजी जाती है। ऐसी स्थिति में कुछ विक्रता ज्वैरी वापस रकने से इंकार कर देते हैं। ऐसी समस्याओं से बचने के लिए बिल के भुगतान से पहले ज्वैलरी के माप और डिजाइन के बारे में पूरी तसल्ली कर लें।



शब्द सामर्थ्य -056

(भागवत साहू)

बाएं से दाएं

1. संघर्ष, दौड़धूप (उर्दू) 5. सुपुत्र, लायक पुत्र 7. ताकतवर, बलशाली 9. खुशबू, सुरभि, सुगंध 10. अकारण, व्यर्थ, बेवजह 12. गर्म तेल आदि में खाद्य वस्तु छोड़कर पकाना 13. यात्रा 15. मृत, जो मर गया हो 16. छोटे कद का, वामन, बौना 18. सांप का सिर, गुण, कला, कौशल 20. निरुत्तर,

बेमिसाल 23. गोल हरे दानों वाला एक प्रसिद्ध पौधा, या इस पौधे की फली 24.माता, जननी 25. संतान, औलाद 26. अधीन, अधीनस्थ, कर्मचारी 27. चिड़िया, खग तरफदार।

ऊपर से नीचे

1.पानी में डूबा हुआ, जल प्लावित 2. पाकेटमार, जेब काटने वाला 3. समाधान, खेत जोतने का यंत्र 4.

औषधालय 6. युक्ति, उपाय 8. गीला, तर, भीगा हुआ 11. झटके से मुंह से आवाज के साथ हवा बाहर आना, बलगम आदि का बाहर आना 14. तुरंत, झटपट 15. स्त्री, नारी, अबला 17. एक और एक चौथाई 19. आदमखोर 21. दुनिया, संसार, जग 22. वर्ष की छः ऋतुओं में एक ऋतु जिसमें मौसम सुहावना रहता है 23. बुद्धि, दिमाग।

शब्द सामर्थ्य क्रमांक 55 का हल

पी	चि	दं	ब	र	म			स
ट		भ	ला	ई		अ	स	म
ना	म			स	मा	धि		झ
	ज		बे		न	का	र	ना
बा	बू		आ	य	क	र		
	र	की	ब				प्र	था
ज			रू	प	क		ज	न
हा		पा		ना	म	ची	न	
ज	हां	प	ना	ह		ता	न	ना

अमित साध और ईशा देओल की फिल्म प्रताप का पहला पोस्टर जारी, रिलीज तारीख भी आई

प्रदीप रंगवानी और यूवी फिल्म्स ने अपनी आगामी थ्रिलर फिल्म प्रताप का दमदार फर्स्ट लुक जारी करने के साथ-साथ फिल्म की रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया है। अमित साध अभिनीत यह फिल्म 20 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।

फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर में अमित साध एक प्रभावशाली पुलिस अधिकारी के रूप में नजर आ रहे हैं। हाथ में बंदूक थामे उनका सख्त और तीखा अंदाज तुरंत ध्यान आकर्षित कर रहा है। इसी के साथ पोस्टर में दिखाई गई टूटी हुई दुनिया संघर्ष, खतरे और रहस्य से भरी कहानी की ओर इशारा करती है, जहां चीजें वैसी नहीं हैं जैसी पहली नजर में दिखाई देती हैं।

पोस्टर पर लिखा दमदार टैगलाइन इस बार निशाना बाहर नहीं, भीतर है। फिल्म के रहस्य और रोमांच को और बढ़ा रहा है। सचिन सराफ द्वारा लिखित और निर्देशित प्रताप एक सम्मानित एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की कहानी है, जिसकी जिंदगी उस समय पूरी तरह बदल जाती है जब उसे उसी कानून का सामना करना पड़ता है, जिसकी रक्षा और पालन वह वर्षों से करता आया है। यह दिलचस्प कहानी कर्तव्य, वफादारी और कानून तथा उसे लागू करने वालों के बीच के संघर्ष को एक रोमांचक थ्रिलर के रूप में प्रस्तुत करती है। अमित साध के साथ फिल्म में ईशा देओल, तिग्मांशु धूलिया, मिलिंद गुणाजी और सीमा बिस्वास जैसे शानदार कलाकार भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। फर्स्ट लुक पोस्टर में फिल्म के प्रमुख किरदारों को टूटे हुए कांच की आकर्षक विजुअल शैली के जरिए दिखाया गया है, जो फिल्म की जटिल और रहस्यमयी दुनिया की झलक तो देता है, लेकिन कहानी के कई राज अभी भी छिपाकर रखता है। अपने दिलचस्प कथानक, दमदार कलाकारों की टोली और प्रभावशाली फर्स्ट लुक के साथ प्रताप एक ऐसी रोमांचक थ्रिलर बनने का संकेत देती है, जहां जो व्यक्ति कभी अपने लक्ष्य का पीछा करता था, अब शायद खुद ही निशाना बन गया है।



राइज एंड फॉल' सीजन 2 में वाइल्ड कार्ड से एंट्री लेगी सोनम मलिक

हरियाणा की युवा अभिनेत्री सोनम मलिक जल्द ही रियलिटी शो राइज एंड फॉल' के दूसरे सीजन में वाइल्ड कार्ड प्रतिभागी के तौर पर नजर आएंगी। शो में उनकी एंट्री की खबर के बाद दर्शकों में उत्सुकता बढ़ गई है। भोजपुरी संगीत जगत में अपनी पहचान बना चुकीं सोनम अब लगातार नए प्रोजेक्ट्स के जरिए मनोरंजन क्षेत्र में अपनी जगह मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं।

सोनम मलिक भोजपुरी संगीत जगत के कई प्रोजेक्ट्स में काम कर चुकी हैं। भोजपुरी के चर्चित गायक और अभिनेता पवन सिंह के साथ उनका पेशेवर जुड़ाव भी उन्हें सुर्खियों में ला चुका है। सोनम ने पवन सिंह के साथ चर्चित गीत %आरा के ओठलाली' में काम किया था। गीत को दर्शकों की अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी और दोनों की जोड़ी को लेकर भी काफी चर्चा हुई थी।

सोनम मलिक उस समय भी चर्चा में आई थीं, जब उन्होंने पवन सिंह के समर्थन में सार्वजनिक तौर पर अपनी बात रखी थी। इसके बाद सामाजिक मंचों पर उनके बयान और पवन सिंह के साथ उनके पेशेवर संबंधों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थीं।

मनोरंजन जगत में यह चर्चा भी रही है कि पवन सिंह ने सोनम के करियर को आगे बढ़ाने में मदद करने की बात कही है। हालांकि, इस संबंध में कोई विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। इसलिए इसे फिलहाल मनोरंजन उद्योग में चल रही चर्चा के तौर पर ही देखा जा रहा है।

भोजपुरी संगीत जगत में काम करने के बाद सोनम मलिक ने चौपाल के मूल हरियाणवी प्रोजेक्ट %डाक खाना' में भी अभिनय किया है। यह प्रोजेक्ट रिलीज हो चुका है। इसमें सोनम के साथ एनडी कुंडू नजर आए थे।

अब सोनम हिंदी सिनेमा में भी कदम रखने की तैयारी में हैं। उनकी आगामी हिंदी फिल्म का नाम महक' बताया जा रहा है। फिल्म को लेकर उनके प्रशंसकों में उत्सुकता बनी हुई है और वे सोनम को हिंदी सिनेमा में नए अंदाज में देखने का इंतजार कर रहे हैं। डाक खाना' के बाद हिंदी फिल्म महक' और अब राइज एंड फॉल' के दूसरे सीजन में वाइल्ड कार्ड प्रवेश को सोनम मलिक के करियर के महत्वपूर्ण पड़ाव के तौर पर देखा जा रहा है। रियलिटी शो में सोनम की चुनौती केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं होगी। उन्हें अपनी रणनीति, खेल और व्यक्तित्व के दम पर अन्य प्रतिभागियों के बीच अपनी जगह बनानी होगी। अब देखना होगा कि शो में उनकी एंट्री मौजूदा समीकरणों को किस तरह प्रभावित करती है और दर्शक उनके नए अंदाज को कितना पसंद करते हैं।

आयुष्मान खुराना के साथ मुपापा में नजर आएंगी अभिनेत्री श्रेया चौधरी

अभिनेता आयुष्मान खुराना की आगामी फिल्म मुपापा' को लेकर नया अपडेट सामने आया है। इस फिल्म में आयुष्मान खुराना के साथ अभिनेत्री श्रेया चौधरी मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। श्रेया को बंदिश बैंडिट्स' और द मेहता बॉयज' जैसे धारावाहिकों के जरिए दर्शकों के बीच पहचान मिली है। अब वह बड़े पर्दे पर आयुष्मान के साथ जोड़ी बनाती दिखाई देंगी।

इसी साल जुलाई में आयुष्मान खुराना के मुपापा' से जुड़ने की खबर सामने आई थी। फिल्म का निर्माण यशराज फिल्म्स और पोशम पा पिक्चर्स मिलकर कर रहे हैं। यशराज फिल्म्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अक्षय विधानी इसके निर्माता हैं, जबकि फिल्म का निर्देशन समीर सक्सेना कर रहे हैं।

श्रेया चौधरी का फिल्म से जुड़ना उनके अभिनय करियर के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। डिजिटल मंच पर अपने काम से दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने के बाद अब वह यशराज फिल्म्स की आगामी रोमांचक फिल्म के जरिए बड़े पर्दे पर दिखाई देंगी। बताया गया है कि यशराज फिल्म्स की प्रतिभा प्रबंधन शाखा ने श्रेया को विशेष प्रबंधन के लिए अनुबंधित भी किया है। इससे उनके पेशेवर सफर में एक नया अध्याय जुड़ गया है।

मुपापा' को निर्माताओं ने एक अलग तरह की सिनेमाघर केंद्रित फिल्म बताया है। फिल्म की कहानी और प्रस्तुति को लेकर फिलहाल ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन निर्माताओं का दावा है



कि यह दर्शकों को नया दृश्य अनुभव देगी और कहानी की शुरुआत से अंत तक उन्हें बांधे रखेगी।

फिल्म के निर्माण में यशराज फिल्म्स और पोशम पा पिक्चर्स का साथ आना भी इसे खास बनाता है। आयुष्मान खुराना की फिल्मों में आमतौर पर अलग विषय और कहानी देखने को मिलती है। ऐसे में मुपापा' में उनकी भूमिका और श्रेया चौधरी के साथ उनकी जोड़ी को लेकर दर्शकों में उत्सुकता बढ़ गई है।

निर्माताओं ने मुपापा' की प्रदर्शन तिथि

भी घोषित कर दी है। यह फिल्म 19 फरवरी 2027 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में प्रदर्शित की जाएगी। फिल्म की कहानी और कलाकारों से जुड़ी अन्य जानकारियों का खुलासा आने वाले दिनों में किए जाने की उम्मीद है।

वहीं, आयुष्मान खुराना की आगामी फिल्मों में सूरज बडजात्या के निर्देशन में बन रही ये प्रेम मोल लिया' भी शामिल है। इस फिल्म को लेकर भी अभिनेता के प्रशंसकों में काफी उत्सुकता बनी हुई है।

सोनाक्षी से एकतरफा प्यार में सनकी आशिक बने जहीर



एकतरफा होता है।

वह स्वीकार करता है कि कभी एकतरफा प्यार हुआ तो टूट जाएगा, इसलिए किरण को भी उससे प्यार करना होगा। यह सुनकर किरण समर से दूरी बनाने के लिए पक्का इरादा कर चुकी है। एक समय पर, वह उससे कहती है कि उसे अकेला छोड़ दे। हालांकि, समर हार मानने से इनकार कर देता है, जिससे संकेत मिलता है कि किरण के प्रति उसका जुनून तो बस शुरू ही हुआ है।

ट्रेलर उनके रिश्ते की असलियत को रहस्यमयी बनाए रखता है। कई सीन में तो हकीकत पर ही शक होता है। अजीब घटनाओं की वजह से किरण और दर्शक, दोनों ही सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि असल में क्या हो रहा है। ऐसे संकेत भी मिलते हैं कि कोई उसकी सोच को प्रभावित कर रहा है और उसे बर्बादी की कगार पर धकेल रहा है। समर का व्यवहार जैसे-जैसे पजेसिव होता जाता है, वैसे-वैसे तनाव बढ़ता जाता है। ट्रेलर एक डरावने मोड़ पर खत्म होता है, जिसमें बेहोश और घायल किरण की झलक देखने को मिलती है।

तू है मेरी किरण का निर्देशन करण रावल ने किया है। इसे विशाल राणा और एशेलॉन प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल अहम भूमिका में हैं। तू है मेरी किरण 23 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल एक बार फिर से बड़े पर्दे पर एक साथ दिखने वाले हैं। वे आगामी फिल्म तू है मेरी किरण में एक साथ दिखेंगे। मेकर्स ने इस रोमांटिक थ्रिलर फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया है। यह एक ऐसे रिश्ते की झलक दिखाता है जिसमें प्यार धीरे-धीरे एक डरावने और जुनूनी मोड़ पर पहुंच जाता है। यह रोमांटिक थ्रिलर मिस्ट्री, सस्पेंस और चौंकाने वाले ट्विस्ट के जरिए एकतरफा प्यार की कहानी दिखाती है।

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने मंगलवार को इंस्टाग्राम हैंडल पर तू है मेरी किरण का ट्रेलर अपलोड किया और कैप्शन

में लिखा, एक कनेक्शन, दो रियलिटी, एक सच्चाई। तू है मेरी किरण। ट्रेलर आ गया है। 23 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

ट्रेलर में सोनाक्षी को किरण और जहीर को समर के तौर पर दिखाया गया है। जिनका रिश्ता आम नहीं लगता। ट्रेलर की शुरुआत जहीर के बॉयज ओवर से होता है, जो समर और किरण के कनेक्शन के बारे में बताता है। समर का मानना है कि उसके और किरण के बीच एक खास कनेक्शन है, लेकिन जिसे वह प्यार कहता है, वह जल्द ही काफी परेशान करने वाला लगने लगता है। क्योंकि उसका प्यार

मानकों पर खरे नहीं उतरे छह खाद्य पदार्थों के सैंपल

नई टिहरी(आरएनएस)। टिहरी जिले के अलग-अलग बाजारों में खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से लिए गए छह खाद्य पदार्थों के नमूने प्रयोगशाला जांच में मानकों के विपरीत पाए हैं। इनमें दही के तीन, दूध, पनीर और मैदा के एक-एक नमूने शामिल हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से इन मामलों में छह खाद्य कारोबारियों के खिलाफ न्याय निर्णायक अधिकारी/ एडीएम की अदालत में वाद दायर किया गया है। मुनिकीरेती तपोवन क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित होटल में एक्सपायरी खाद्य सामग्री मिलने के मामले में न्यायालय ने होटल संचालक पर दो लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी शारदा शर्मा ने बताया कि अलग-अलग तिथियों में बाजारों में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांचने के लिए अभियान चलाया गया था। इस दौरान भरे गए सैंपलों को प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया था। प्रयोगशाला जांच में छह नमूने मानकों पर खरे नहीं उतरे। संबंधित कारोबारियों को जांच रिपोर्ट पर अपना पक्ष रखने और उसे चुनौती देने का मौके दिया गया था। दो कारोबारियों की ओर से अपील में प्रस्तुत तथ्य संतोषजनक नहीं पाए गए और उनकी अपील खारिज कर दी गई। सभी छह मामलों में न्यायालय में अभियोजन की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी शारदा ने बताया कि बीते 20 अगस्त को मुनिकीरेती तपोवन में स्थित एक प्रतिष्ठित होटल में जांच के दौरान काफी मात्रा में एक्सपायरी खाद्य सामग्री मिली थी। सुनवाई के बाद न्यायालय ने होटल संचालक पर दो लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है।

गौचर मेले की तैयारियों को लेकर हुई बैठक

चमोली(आरएनएस)। 14 नवंबर से 20 नवंबर तक होने वाले 74वें राजस्त्रीय गौचर मेले को भव्य बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। मेले को इस बार सोशल मीडिया पर दिखाए जाने की कवायद शुरू हो गई है। इससे देश और विदेश में रह रहे प्रवासी भी गौचर मेले को देख सकेंगे। गौचर नगर पालिका सभागार में आयोजित बैठक में मेले की 21 समितियों का पुनर्गठन किया गया। बैठक में विधायक अनिल नौटियाल ने कहा कि समितियों में नाम लिखवाने तक ही जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए बल्कि इस राज्यस्तरीय मेले को और भव्य कैसे बना सकते हैं इसके लिए काम करना जरूरी है। एसडीएम और मेलाधिकारी अलकेश नौडियाल ने कहा कि इस बार गौचर मेला का सोशल मीडिया एकाउंट बनाया गया है। इससे मेला सोशल मीडिया पर भी दिखाया जाएगा। इससे मेले की पहचान राज्यस्तर से राष्ट्रीय और विश्व स्तर तक होगी। बैठक में नपा अध्यक्ष संदीप नेगी, सुनील पंवार, विजय डिमरी, प्रमुख दीपिका मैखुरी सहित कई लोगों ने अपने सुझाव रखे। इस अवसर पर तहसीलदार सुधा डोभाल, सीओ त्रिवेन्द्र सिंह राणा, एसएचओ विनोद थपलियाल, गणेश शाह, रेखा बिष्ट आदि मौजूद थे।

सू- दोकू क्र.056											
		3					7				
9				6		3		8			
	7		9		5		6				
						1		9			
3		8		7			5				
	1		3		9			7			
		2		8		7					
	8				2		4	3			
			1								
नियम			सू-दोकू क्र.55 का हल								
1. कुल 81 वर्ग है,जिसमें 9वर्गों का एक खंड बनता है। 2. हर खाली वर्ग में 1से 9 के बीच का कोई एक अंक र सकते है। 3. बाएं से दाएं और उपर से नीचे के प्रत्येक कालम,कतार और खंड में 1से9अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते है।			5	2	4	9	6	7	8	1	3
			3	6	7	4	1	8	2	9	5
			8	1	9	3	2	5	4	6	7
			6	3	5	1	9	4	7	2	8
			7	9	8	5	3	2	6	4	1
			2	4	1	7	8	6	5	3	9
			4	5	3	6	7	9	1	8	2
			9	8	6	2	5	1	3	7	4
			1	7	2	8	4	3	9	5	6

गैरसैंण से सियासी संदेश देगी धामी सरकार

कार्यालय संवाददाता
देहरादून। उत्तराखंड में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण एक बार फिर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने विधानसभा का अगला सत्र गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में आयोजित करने का निर्णय लिया है। सत्र 27 अक्टूबर से शुरू होगा। विधानसभा सचिवालय की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। सत्र के दौरान सरकार करीब पांच हजार करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट भी पेश कर सकती है। ऐसे में यह सत्र विधायी कामकाज के साथ-साथ चुनावी वर्ष से पहले सरकार की राजनीतिक प्राथमिकताओं और विपक्ष की रणनीति के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

गैरसैंण उत्तराखंड की राजनीति में केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि पर्वतीय क्षेत्रों की आकांक्षाओं और राजधानी से जुड़े भावनात्मक सवालों का प्रतीक रहा है। राज्य गठन के बाद से ही गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग समय-समय पर उठती रही है। सरकारों ने इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी का दर्जा देकर यहां विधानसभा सत्र आयोजित करने की परंपरा को आगे बढ़ाया, लेकिन राजधानी के सवाल का स्थायी समाधान अब भी राजनीतिक बहस का विषय बना हुआ है।

आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए गैरसैंण में सत्र आयोजित करने का राजनीतिक महत्व भी है। पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार, पलायन, स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा, सड़क संपर्क और स्थानीय अर्थव्यवस्था से जुड़े सवाल लंबे समय से चर्चा में हैं। गैरसैंण में सदन की बैठक के

माध्यम से सरकार इन मुद्दों पर अपनी प्रतिबद्धता का संदेश दे सकती है। हालांकि, पहाड़ की जनता के लिए प्रतीकात्मक घोषणाओं से अधिक महत्वपूर्ण यह होगा कि इन समस्याओं के समाधान की दिशा में कितनी ठोस प्रगति हुई है।

सरकार के सामने चुनौती यह भी होगी

◆27 अक्टूबर से भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में होगा विधानसभा सत्र
◆पांच हजार करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट लाने की है तैयारी
◆चुनाव से पहले पहाड़ के विकास, क्षेत्रीय असंतुलन पर फोकस
◆जनसमस्याओं पर प्रदेश सरकार को घेरने की तैयारी में है विपक्ष

कि गैरसैंण में सत्र आयोजित करने का संदेश केवल औपचारिकता बनकर न रह जाए। पर्वतीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार, दूरस्थ गांवों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर और पलायन पर प्रभावी नियंत्रण जैसे विषयों पर सरकार को अपनी उपलब्धियों और योजनाओं का स्पष्ट ब्योरा देना पड़ सकता है। सत्र में करीब पांच हजार करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट लाए जाने की तैयारी है। इसके लिए विभिन्न विभागों से बजट प्रस्ताव मांगे जा चुके हैं। अनुपूरक बजट के जरिये चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की जरूरत वाली योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए प्रावधान किए जा सकते हैं।

अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि अतिरिक्त बजट का कितना हिस्सा विकास कार्यों, आधारभूत ढांचे, जनकल्याणकारी योजनाओं और पर्वतीय क्षेत्रों की जरूरतों पर खर्च करने का प्रस्ताव रखा जाता है। चुनाव से पहले पेश होने वाले इस बजट

में सरकार की प्राथमिकताएं राजनीतिक विमर्श को प्रभावित कर सकती हैं। विपक्ष भी बजट के प्रावधानों के आधार पर सरकार को घेरने की कोशिश कर सकता है। विधानसभा सत्र में विपक्ष के सामने बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाओं और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन जैसे मुद्दे उठाने का अवसर होगा। विपक्ष यह सवाल उठा सकता है कि सरकार के दावों का लाभ दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों तक कितना पहुंचा है और गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए जाने के बाद वहां प्रशासनिक गतिविधियों को अपेक्षित गति क्यों नहीं मिली।

हालांकि, विपक्ष की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह सदन में तथ्यों और ठोस सवालों के साथ सरकार को कितना जवाबदेह बना पाता है। वहीं सरकार के सामने भी अपनी योजनाओं, खर्च और विकास संबंधी दावों को स्पष्ट करने की चुनौती रहेगी। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण के अनुसार, विधानसभा सचिवालय गैरसैंण में सत्र आयोजित करने के लिए तैयार है और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। 27 अक्टूबर को सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी।

कुल मिलाकर, गैरसैंण में प्रस्तावित यह सत्र सरकार और विपक्ष दोनों के लिए महत्वपूर्ण अवसर होगा। सरकार जहां विकास और जनकल्याण के एजेंडे को सामने रखने की कोशिश करेगी, वहीं विपक्ष सरकारी दावों की जमीनी हकीकत पर सवाल उठा सकता है। चुनावी वर्ष में गैरसैंण से निकलने वाला राजनीतिक संदेश कितना प्रभावी होगा, यह सदन में होने वाली बहस और लिए जाने वाले फैसलों से तय होगा।

31 खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं मिली

कोटद्वार(आरएनएस)। त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने 12 और 13 अक्टूबर को फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स के माध्यम से 145 खाद्य पदार्थों की मौके पर जांच की। जांच में 31 खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं मिली। अधो मानक खाद्य पदार्थों के संबंध में संबंधित कारोबारियों को मौके पर ही सुधार करने के निर्देश दिए गए। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखंड और डीएम पौड़ी गढ़वाल के निर्देश पर डिप्टी कमिश्नर लैब वीरेंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान दूध से बने 21 पदार्थों, मिठाई के 42, तेल एवं वसा के 15, मसालों के 33, अनाज एवं अनाज से बने 14 और अन्य श्रेणियों के 20 खाद्य पदार्थों की जांच की गई। इस दौरान करीब 31 खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं मिली। टीम ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है। टीम में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी कोटद्वार संदीप मिश्रा, फूड एनालिस्ट जितेंद्र भंडारी, लैब असिस्टेंट गौरव नेगी सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।

केदारनाथ धाम में अस्थायी कर्मचारियों का आंदोलन, मांगें पूरी न होने पर अनशन का ऐलान

रुद्र प्रयाग(आरएनएस)। श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के करीब 300 अस्थायी कर्मचारियों ने वर्षों पुरानी मांगों का निराकरण न होने पर आंदोलन का ऐलान किया है। कर्मचारियों का आरोप है कि दशकों से सेवा देने के बावजूद उनकी मांगों की अनदेखी की जा रही है और ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले करीब एक दर्जन कर्मचारियों के आश्रितों को भी आर्थिक सहायता नहीं मिली। इसी के विरोध में कर्मचारियों ने 12 अक्टूबर से एक सप्ताह तक क्रमिक अनशन शुरू करने और मांगें पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की

चेतावनी दी है। श्री बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अधीन करीब 300 (तीन सौ) अस्थायी कार्मिक दशकों से श्री धामों में तैनात हैं और उनके भरोसे ही पूरी यात्रा का संचालन विभाग द्वारा किया जाता रहा है। दशकों से सेवा दे रहे इन कार्मिकों की सुध विभाग द्वारा बहुत याचना के बाद भी नहीं ली जा रही है और अमानवीय हर्दों को पार कर विभाग में कार्य करते हुवे परम धाम को गमन कर गए करीब एक दर्जन कार्मिकों के परिवारों/आश्रितों को मृत्यु पश्चात भी एक धेले की सहायता नहीं दी गयी।

पूर्व में हमारे द्वारा इस कार्यालय को अपनी मांगों के समयबद्ध निराकरण न होने की स्थिति में आन्दोलन को बाध्य होना सूचित किया गया था और विभाग ने अपना पुराना रूख बरकरार रखते हुवे कुछ भी नहीं किया। अतः अब हम सभी स्थिर वेतन कार्मिक भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त अपने मूल अधिकारों की रक्षा एवं प्रयोग करते हुवे एक सप्ताह का शांतिपूर्वक क्रमिक अनशन पूर्वाहन ॥ बजे से और अपराह्न बजे तक मंदिर प्रांगण में कल से एक सप्ताह तक करेंगे, तब तक भी निराकरण न होने की स्थिति में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को बाध्य होंगे।

दुष्यंत कुमार गौतम की नियुक्ति पर पुनर्विचार की मांग

◆सिक्किम विश्वविद्यालय छात्र संघ ने उठाए सवाल

हमारे संवाददाता
सिक्किम। उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े कथित वीआईपी प्रकरण को लेकर अब सिक्किम में भी सवाल उठने लगे हैं। सिक्किम विश्वविद्यालय छात्र संघ ने 12 अक्टूबर 2026 को दुष्यंत कुमार गौतम को सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किए जाने के संदर्भ में चिंता व्यक्त करते हुए उनकी नियुक्ति पर पुनर्विचार की अपील की है।

छात्र संघ की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े आरोपों और सार्वजनिक रूप से उठाए जा रहे सवालों के मद्देनजर इस नियुक्ति पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। संघ ने सिक्किम सरकार और आम जनता का ध्यान इस मामले की ओर आकर्षित करते हुए संवैधानिक पदों पर नियुक्तियों में पारदर्शिता और जवाबदेही को आवश्यक बताया है।

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर से जुड़ी रहीं उर्मिला सनावर ने कथित ऑडियो क्लिप के माध्यम से दुष्यंत कुमार गौतम का नाम कथित वीआईपी के रूप में लिया था। हालांकि, ये आरोप अदालत में प्रमाणित नहीं हुए हैं। गौतम ने आरोपों से इनकार किया है और मानहानि की कानूनी कार्यवाही भी शुरू की है। छात्र संघ ने अंकिता भंडारी के परिवार की ओर से कथित वीआईपी की पहचान और संबंधित कॉल डिटेल रिकॉर्ड की उपलब्धता को लेकर उठाए गए सवालों का भी उल्लेख किया है। संघ का कहना है कि मामले से जुड़े सभी पहलुओं की सक्षम एजेंसियों द्वारा निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, ताकि तथ्यों की स्थिति स्पष्ट हो सके।

सिक्किम विश्वविद्यालय छात्र संघ ने सक्षम अधिकारियों से अपील की है कि संबंधित आरोपों की पूरी तरह जांच होने और जांच की स्थिति स्पष्ट होने तक राज्यपाल की नियुक्ति पर पुनर्विचार किया जाए। संघ ने इसे व्यापक जनहित और अंकिता भंडारी के परिवार को न्याय दिलाने की मांग के प्रति एकजुटता से जुड़ा विषय बताया है।

अंकिता प्रकरण पर भाजपा का...

◀ पृष्ठ 2 का शेष

स्पष्ट करने की कोशिश भी माना जा सकता है। हालांकि, किसी भी दल की राजनीतिक रणनीति से अलग इस प्रकरण का मूल प्रश्न न्याय है। गिरफ्तारी, जांच और अभियोजन आपराधिक न्याय प्रक्रिया के महत्वपूर्ण हिस्से हैं, लेकिन जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए पारदर्शिता और उठने वाले सवालों का तथ्यात्मक समाधान भी आवश्यक है। अंकिता प्रकरण में भाजपा ने सरकार की कार्रवाई का पक्ष मजबूती से रखा है, लेकिन राजनीतिक बहस का अंतिम फैसला बयानों से नहीं होगा। सरकार के दावों, न्यायिक प्रक्रिया और पीड़ित परिवार की मांगों के बीच कितना भरोसेमंद संवाद बनता है, यही तय करेगा कि इस संवेदनशील मामले पर उठ रहे सवालों का समाधान किस दिशा में आगे बढ़ता है।

सियासत में ‘खौफ’ कठघरे में सता..

◀ पृष्ठ 2 का शेष

तथ्यों के आधार पर स्थिति स्पष्ट करें, न कि इसे केवल विपक्ष की राजनीति बताकर खारिज कर दें। हालांकि, विधायक ने गैरसैन्य सत्र के दौरान कठोर कदम उठाने की जो चेतावनी दी है, उसका सटीक आशय स्पष्ट होना जरूरी है। इसे लेकर अटकलों के बजाय उनकी शिकायत और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। संबंधित अधिकारियों को उनसे तत्काल संवाद कर उनकी बात सुननी चाहिए।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि वह इस प्रकरण से कैसे निपटती है। क्या विधायक की शिकायत की निष्पक्ष जांच होगी? क्या फोन टैपिंग के दावे की सत्यता सामने लाई जाएगी? क्या संभावित सुरक्षा खतरे का आकलन किया जाएगा? और क्या सरकार इन सवालों पर सार्वजनिक रूप से स्थिति स्पष्ट करेगी? ये सवाल किसी एक दल के राजनीतिक फायदे या नुकसान से बड़े हैं। यदि शिकायत में तथ्य हैं, तो कार्रवाई होनी चाहिए। यदि आरोपों की पुष्टि नहीं होती, तो जांच के निष्कर्ष सामने आने चाहिए। दोनों ही स्थितियों में पारदर्शिता जरूरी है। गैरसैन्य सत्र से पहले सुमित हृदयेश के आरोपों ने सरकार के सामने राजनीतिक और प्रशासनिक, दोनों मोर्चों पर चुनौती खड़ी कर दी है। अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि सरकार आरोपों का जवाब कैसे देती है और पुलिस प्रशासन मामले की जांच में कितनी तत्परता दिखाता है। फिलहाल इतना तय है कि यह मामला केवल एक विधायक के भावुक बयान तक सीमित नहीं रहेगा। यदि कांग्रेस इसे सदन में उठाती है, तो गैरसैन्य में कानून-व्यवस्था, राजनीतिक निगरानी और जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा पर तीखी बहस हो सकती है। लेकिन उस बहस की विश्वसनीयता इसी में होगी कि आरोपों को तथ्यों की कसौटी पर परखा जाए और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाए।

अंकिता भण्डारी हत्याकांड को लेकर पुलिस की सफाई!

संवाददाता
देहरादून। अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध एवं कानून व्यवस्था), उत्तराखंड डॉ. वी. मुरुगेशन ने गुरुवार को पुलिस मुख्यालय, देहरादून में आयोजित प्रेस वार्ता में अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच एवं न्यायिक कार्यवाही के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।

डॉ. मुरुगेशन ने बताया कि वर्ष 2022 में ऋषिकेश के निकट वनंतरा रिजॉर्ट में कार्यरत युवती स्व. अंकिता भंडारी के साथ हुई दुखद घटना में उत्तराखंड पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई की। पुलिस टीमों ने आपसी समन्वय से घटना सामने आने के 24 घंटे के भीतर तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया था।

अपर पुलिस महानिदेशक ने बताया कि घटना की गंभीरता एवं संवेदनशीलता को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर तत्काल विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया। डीआईजी स्तर की महिला आईपीएस अधिकारी को एसआईटी का अध्यक्ष बनाया गया, ताकि प्रकरण की गहन एवं प्रभावी जांच सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने बताया कि एसआईटी ने प्रकरण की जांच के दौरान डिजिटल, तकनीकी, फॉरेंसिक एवं भौतिक साक्ष्यों का गहनता से संकलन किया। इसके अतिरिक्त अभियुक्तों से विस्तृत पूछताछ, फॉरेंसिक रिपोर्टें एवं गवाहों के बयानों सहित सभी महत्वपूर्ण साक्ष्यों का गहन विश्लेषण किया गया। एसआईटी ने 88

दिनों में जांच पूरी कर लगभग 500 पृष्ठों का विस्तृत आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया।

डॉ. मुरुगेशन ने बताया कि उत्तराखंड शासन द्वारा प्रकरण की त्वरित सुनवाई एवं प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रयास किए गए। एसआईटी द्वारा संकलित ठोस साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 30 मई 2025 को कोर्टद्वारा स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर एवं अंकित गुप्ता को दोषी करार देते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। तीनों दोषी वर्तमान में जेल में बंद हैं और आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।

ट्रक पेड़ से टकराया, सहचालक की मौत, चालक घायल

हमारे संवाददाता
देहरादून। सड़क हादसे में आज सुबह एक ट्रक के पेड़ से टकरा जाने से जहां सहचालक की मौत हो गयी वहीं चालक घायल हुआ है। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घायल चालक को अस्पताल पहुंचाया जहां उसका उपचार जारी है।

राजधानी देहरादून के आशारोड़ी क्षेत्र में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज भी एक बार फिर एक ट्रक के अनियंत्रित होने के बाद वह पेड़ से जा टकराया। जिस कारण सहचालक की मौत होने की सूचना है। जबकि चालक गम्भीर रूप से घायल हुआ है। वहीं



सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर चालक को अस्पताल भिजवाया जहां उसका उपचार जारी है।

बता दे कि बीते कुछ समय से आशारोड़ी क्षेत्र में सड़क हादसों की संख्या में इजाफा हुआ है।

थत्यूड़ पुलिस ने 04.09 ग्राम स्मैक के साथ किया गिरफ्तार

संवाददाता
टिहरी। पुलिस ने स्मैक के साथ एक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसको न्यायालय में पेश किया जहां से उसको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

मिली जानकारी के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक टिहरी गढ़वाल, श्रीमती श्वेता चौबे के निर्देशन में जनपद को नशामुक्त बनाने एवं मादक पदार्थों की

तस्करी व बिक्री की रोकथाम हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में ऑपरेशन प्रहार अभियान के तहत थत्यूड़ पुलिस को नशा तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई में सफलता मिली है। थत्यूड़ पुलिस ने वाहन एक्टिवा स्कूटर से अवैध स्मैक की तस्करी/परिवहन करते हुए एक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार की पहचान हर्षित पुत्र रोशन लाल शाह,

निवासी बड़ेथी चुंगी, पोस्ट मातली, थाना कोतवाली उत्तरकाशी, जनपद उत्तरकाशी के रूप में हुई है। उसके कब्जे से 04.09 ग्राम स्मैक एवं तस्करी में प्रयुक्त एक्टिवा स्कूटर बरामद किया गया। जिसके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने उसको न्यायालय में पेश किया जहां से उसको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

ढोल-दमाऊ की गूंज में निकली भव्य राम बारात

हमारे संवाददाता
देहरादून। श्री रामकृष्ण लीला समिति द्वारा श्री गुरु नानक मैदान, रसकोर्स में आयोजित ‘भव्य रामलीला महोत्सव-2026’ का चतुर्थ दिवस ‘सर्वधर्म सद्भाव दिवस’ के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बदरीनाथ विधायक लखपत बुटोला उपस्थित रहे।

दिन की शुरुआत भगवान श्रीराम की भव्य बारात से हुई, जिसमें ढोल-दमाऊ, ढोल-नगाड़ों और पारंपरिक वाद्ययंत्रों की गूंज ने पूरे वातावरण को भक्तिमय एवं उत्सवमय बना दिया। इसके पश्चात डिजिटल दरबार, आकर्षक प्रकाश व्यवस्था और आधुनिक लेजर एंड साउंड शो ने पारंपरिक रामलीला को भव्य एवं जीवंत स्वरूप प्रदान किया। मुख्य अतिथि लखपत बुटोला ने कहा कि भगवान श्रीराम का जीवन त्याग, मर्यादा, कर्तव्य और आदर्शों की प्रेरणा देता है। उन्होंने श्री रामकृष्ण लीला समिति टिहरी 1952, देहरादून (पंजी.)

रामलीला के मंचन में कैकेयी द्वारा राजा दशरथ से दो वरदान मांगने का



◆दशरथ-कैकेयी संवाद ने किया भावविभोर

प्रसंग प्रस्तुत किया गया, जिसमें भरत के लिए राजगद्दी और भगवान श्रीराम के लिए चौदह वर्ष का वनवास मांगा गया। इस भावुक प्रसंग ने दर्शकों को भावविभोर कर दिया। डिजिटल दरबार, आकर्षक प्रकाश व्यवस्था और आधुनिक लेजर एंड साउंड शो ने पारंपरिक रामलीला को भव्य एवं जीवंत स्वरूप प्रदान किया।

मुख्य अतिथि लखपत बुटोला ने कहा कि भगवान श्रीराम का जीवन त्याग, मर्यादा, कर्तव्य और आदर्शों की प्रेरणा देता है। उन्होंने श्री रामकृष्ण लीला समिति टिहरी 1952, देहरादून (पंजी.)

के अध्यक्ष अभिनव थापर के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि पुरानी टिहरी की ऐतिहासिक रामलीला को देहरादून में भव्य स्वरूप में पुनर्जीवित करना सराहनीय पहल है। ऐसे आयोजन हमारी सांस्कृतिक विरासत को जीवंत रखने के साथ समाज में नैतिक मूल्यों, आपसी सद्भाव और भाईचारे को मजबूत करते हैं।

समिति के अध्यक्ष अभिनव थापर ने कहा कि रामलीला भारतीय संस्कृति, सामाजिक समरसता और मानवीय मूल्यों का प्रतीक है। ‘सर्वधर्म सद्भाव दिवस’ के माध्यम से समाज में आपसी प्रेम, भाईचारे, सद्भाव और एकता का संदेश दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि श्री रामकृष्ण लीला समिति टिहरी 1952, देहरादून (पंजी.) का उद्देश्य पुरानी टिहरी की ऐतिहासिक रामलीला की परंपरा को जीवंत रखने के साथ उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है।

मेधावी विद्यार्थी उत्तराखंड के उज्ज्वल भविष्य के आधार स्तंभ: धामी

मुख्यमंत्री ने 63 मेधावी छात्र-छात्राओं और छह प्रधानाचार्यों को किया सम्मानित



संवाददाता

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित पं. दीनदयाल उपाध्याय शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार वितरण समारोह में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की वर्ष 2026 की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं में शीर्ष 10 स्थान प्राप्त करने वाले 63 मेधावी छात्र-छात्राओं तथा उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देने वाले छह विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को सम्मानित किया।

समारोह में हाईस्कूल के 38 और इंटरमीडिएट के 25 मेधावी छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। हाईस्कूल परीक्षा में अक्षत गोपाल ने 98.20 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल

किया, जबकि इंटरमीडिएट परीक्षा में गीतिका पंत एवं सुशीला मेहंदीरता ने संयुक्त रूप से 98 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया। इसके साथ ही हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट स्तर पर उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देने वाले तीन-तीन विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को प्रशस्ति पत्र एवं मुख्यमंत्री ट्रॉफी से सम्मानित किया गया।

मुख्यमंत्री ने सभी सम्मानित मेधावी छात्र-छात्राओं एवं प्रधानाचार्यों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2026 में प्रदेश का हाईस्कूल परीक्षाफल 92.10 प्रतिशत तथा इंटरमीडिएट का परीक्षाफल 85.11 प्रतिशत रहा, जो सराहनीय उपलब्धि है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेश के विद्यार्थी भविष्य

में भी अपनी प्रतिभा और परिश्रम के बल पर राज्य एवं देश का नाम रोशन करेंगे।

मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय का स्मरण करते हुए कहा कि वे एकात्म मानववाद और अंत्योदय के प्रणेता होने के साथ ही महान विचारक, शिक्षाविद् और समाजसेवी थे। उनका मानना था कि शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उसमें राष्ट्रप्रेम, नैतिक मूल्यों, सामाजिक समरसता और व्यावहारिक ज्ञान का भी समावेश होना चाहिए। उनके विचार आज भी एक शिक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर समाज के निर्माण की प्रेरणा देते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के माध्यम से देश की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक, व्यावहारिक और गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उत्तराखंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाले अग्रणी राज्यों में शामिल है। राज्य सरकार शिक्षा में नवाचार, डिजिटल लर्निंग और भारतीय जीवन मूल्यों को बढ़ावा देने के साथ ही विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दे रही है।

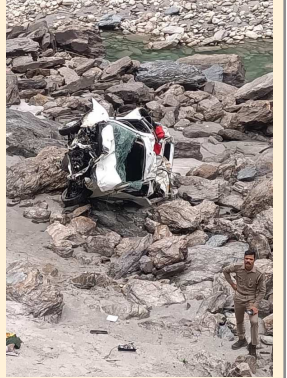
खाई में गिरी कार, दो की मौत तीन गम्भीर घायल

हमारे संवाददाता

टिहरी। चंडीगढ़ से रुद्रप्रयाग जा रही मारुति सुजुकी वैगनआर कार ग्राम पाली स्थित रिवर व्यू कैफे एंड रेस्टोरेंट के समीप, देवप्रयाग से लगभग 4 किलोमीटर श्रीनगर की ओर अनियंत्रित होकर सड़क से करीब 150 मीटर नीचे नदी किनारे जा गिरी। वाहन में चालक सहित कुल पाँच व्यक्ति सवार थे। दुर्घटना में तीन व्यक्ति घायल हो गए, जबकि चालक सहित दो लोगों की मृत्यु हो गई। दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर एसडीआरएफ पोस्ट ब्यासी से उपनिरीक्षक सावर सिंह के नेतृत्व में तथा एसडीआरएफ श्रीनगर टीम निरीक्षक मंजरी नेगी के नेतृत्व में रेस्क्यू टीम तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई।

एसडीआरएफ टीमों के घटनास्थल पर पहुँचने से पूर्व ही जिला पुलिस एवं स्थानीय लोगों द्वारा तीनों घायलों को खाई से बाहर निकाल लिया गया था। इसके बाद उन्हें 108 एंबुलेंस के माध्यम से उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। घटनास्थल पर पहुँचने के उपरांत एसडीआरएफ टीमों द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान वाहन में फँसे दोनों व्यक्तियों (एक पुरुष एवं एक महिला) के शव टीम द्वारा बाहर निकाले गए। घटनास्थल की भौगोलिक परिस्थितियों एवं नदी मार्ग को देखते हुए दोनों शवों को राफ्ट के माध्यम से नदी पार कर देवप्रयाग पहुँचाया गया, जहाँ आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया।

घायलों के नाम उत्तम सिंह, पुत्र मोहन सिंह, निवासी ग्राम लाडोली, रुद्रप्रयाग, उम्र 33 वर्ष, टीशा रावत, पुत्र लक्ष्मण सिंह रावत, निवासी ग्राम बीना, थाना एवं जिला रुद्रप्रयाग, उम्र 18 वर्ष व सुनीता देवी, पत्नी श्री लक्ष्मण सिंह रावत, निवासी ग्राम बीना, थाना एवं जिला रुद्रप्रयाग, उम्र 45 वर्ष वहीं मृतकों के नाम सत्येश्वरी देवी, पत्नी हुकम सिंह चौहान, निवासी किमखाल, थाना कर्णप्रयाग, जिला चमोली, उम्र 72 वर्ष व अनिल, वाहन चालक बताये जा रहे हैं।



आमिर खान के भांजे को पुलिस ने दिया भारत छोड़ने का नोटिस

हमारे संवाददाता

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता और आमिर खान के भांजे इमरान खान विवादों में घिर गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुंबई पुलिस ने अभिनेता को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया है। बताया जा रहा है कि इमरान खान क्रांति मैदान में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आयोजित प्रदर्शन में शामिल हुए थे। अमेरिकी नागरिकता और ओसीआई कार्ड को लेकर भी मामला चर्चा में है। हालांकि, नोटिस के आधार और पुलिस की आधिकारिक स्थिति की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है।

गेस्ट हाउस में फंदे से लटका मिला यूट्यूबर का शव!

हमारे संवाददाता

हरिद्वार। कलियर स्थित एक गेस्ट हाउस में आज सुबह मुजफ्फरनगर निवासी 32 वर्षीय यूट्यूबर आतिफ का शव कमरे में पंखे से लटका मिला। घटना की सूचना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है।

जानकारी के अनुसार मुजफ्फरनगर जिले के गांव निराना निवासी आतिफ मुजफ्फरनगर में किराये के कमरे में रहता था। वह इंट्राग्राम पर वीडियो बनाता था। बताया जा रहा है कि वह एक युवती और उसके भाई के साथ



रहता था। युवती से किसी बात को लेकर उसकी नाराजगी हो गई थी। इसके बाद बुधवार रात करीब 11 बजे आतिफ कलियर पहुंचा और एक गेस्ट हाउस में कमरा किराये पर ले लिया। बताया गया कि आज सुबह करीब पांच बजे युवती ने आतिफ को वीडियो कॉल की। इस दौरान आतिफ ने कथित तौर पर फंदे से लटककर आत्महत्या करने की बात कही। युवती ने दूसरे मोबाइल फोन से वीडियो कॉल के जरिये आतिफ के भाई को घटना दिखाई। इसके बाद भाई ने वीडियो का

स्क्रीनशॉट लेकर परिजनों को भेज दिया। घटना की जानकारी मिलने पर आतिफ के परिजन कलियर कोतवाली पहुंचे और पुलिस को पूरे मामले से अवगत कराया। परिजनों से मिली जानकारी और लोकेशन के आधार पर पुलिस गेस्ट हाउस पहुंची। वहां कमरे में आतिफ का शव पंखे से लटका मिला। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक जानकारी जुटाई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने की कार्रवाई की। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक कमल मोहन भंडारी ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

दून पुलिस की नाक के नीचे 18 साल रहा 23 मुकदमों का आरोपी

हमारे संवाददाता

देहरादून। लोगों के सत्यापन के लिए पुलिस अभियान चलाती रही और राजस्थान के सीकर में 23 मुकदमों में फरार आरोपी कल्याण सिंह देहरादून में करीब 18 साल तक ठिकाना बनाए रहा। वह यहां परिवार के साथ रहता था, प्रेमनगर में मकान बनवा लिया था और स्थानीय पते पर राशन कार्ड समेत दूसरे दस्तावेज भी तैयार करा लिए थे। इस दौरान वह देश के अलग-अलग शहरों में कोचिंग संस्थानों में शिक्षक की नौकरी करता रहा। हैरानी की बात यह है कि उसे पकड़ने के लिए आखिरकार राजस्थान पुलिस को देहरादून आना पड़ा। सीकर पुलिस की टीम एयरटेल फाइबर

टेक्नीशियन बनकर उसके घर पहुंची और दबोचकर अपने साथ ले गई।

जानकारी के अनुसार कल्याण सिंह राजस्थान के जालोर जिले के भोरटा गांव का रहने वाला है। आरोप है कि उसने अपने साथी विकास सक्सेना के साथ मिलकर सीकर में विद्यार्थियों को बीएड की डिग्री दिलाने के नाम पर लाखों रुपये की ठगी की। वर्ष 2008 से 2013 के बीच सीकर के कोतवाली थाने में दोनों के खिलाफ कुल 23 मुकदमे दर्ज हुए।

विकास सक्सेना पुलिस की गिरफ्त में आ गया, लेकिन कल्याण सिंह फरार हो गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने अपने गांव और रिश्तेदारों से संपर्क तक बंद कर दिया। सीकर से भागने के



◆फाइबर टेक्नीशियन बनकर पहुंची राजस्थान पुलिस ने दबोचा

बाद कल्याण सिंह देहरादून पहुंचा। शुरुआत में किराये के मकान में रहकर कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने लगा। वर्ष 2013 तक उसने दूनविद्या, एड्युट्रीम समेत कई कोचिंग संस्थानों में पढ़ाया। इसके बाद नोएडा, अलीगढ़, महाराष्ट्र, चेन्नई, वाराणसी, मध्य प्रदेश और सिलीगुड़ी में

अलग-अलग संस्थानों से जुड़ा। वर्ष 2014 में वह अलीगढ़ में आकाश कोचिंग से जुड़ा और करीब तीन साल तक पढ़ाया। वर्ष 2017 में महाराष्ट्र के अमरावती स्थित आकाश कोचिंग में नौकरी की। वर्ष 2018 में घर पर विद्यार्थियों को पढ़ाने लगा। वर्ष 2019 में चेन्नई के एक निजी कोचिंग संस्थान में काम करने लगा। सीकर पुलिस कल्याण सिंह की तलाश में उसके गांव और रिश्तेदारों के यहां कई बार दबिश दे चुकी थी, लेकिन वह हाथ नहीं आया। इस बार जयपुर रेंज के आइजी राहुल प्रकाश की टीम और सीकर कोतवाली पुलिस ने तकनीकी जानकारीयों तथा मिली सूचना के आधार पर उसकी तलाश की।

आर.एन.आई.- 59626/94

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक श्रीमती पुष्पा कांति कुमार द्वारा दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग घंटाघर, देहरादून से प्रकाशित तथा अवि प्रिंटर्स 21 ईसी रोड, देहरादून से मुद्रित।

प्रधान संपादक
कांति कुमार

संपादक
पुष्पा कांति कुमार
समाचार संपादक
आनंद कांति कुमार

कानूनी सलाहकार:
वी के अरोड़ा, एडवोकेट
बैजनाथ, एडवोकेट

कार्यालय: दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग देहरादून।
मो. 9358134808

नोट: सभी विवादों के लिये देहरादून न्यायालय ही मान्य होगा, प्रकाशित सामग्रियों के लिए प्रिंटर्स की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।